द्वारा कितने व्यक्तियों को मकान या भूमि आबंटित की गई है ;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिन्हें अभी भी निबटाया जाना है; और

(ग) पिछले दो वर्षों में किन-किन देशों से आए हुए निष्क्रांतों को भूमि तथा मकान आदि आबंटित किए गए हैं ?

†[ALLOTMENT OF LAND TO EVACUEES

*269. SHRI SURAJ PRASAD : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION/**श्रम और पुनर्वास मंत्री** be pleased to state :

(a) the number of persons who have been allotted houses or land by the Settlement Commissioner during the last two years ;

(b) the number of cases that are yet to be settled; and

(c) the names of the countries, the evacuees of which have been allotted land and houses etc. within the last two years?]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह अनुमान है कि यह प्रश्न उन मकानों और भूमियों के बारे में है जिन्हें कि विस्थापित व्यक्ति (प्रति कर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नियुक्त किए गए बन्दोबस्त आयुक्तों द्वारा नीलाम या टेंडर के अलावा किसी अन्य रूप से हस्तांतरित किया गया है । इसी अनुमान के आधार पर जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION **श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री** (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) to (c) It is presumed that the Question refers to transfer of houses and land, otherwise than by auction or tender, by the Settlement Commissioners appointed under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954. Information is being collected on this assumption and will be laid on the Table of the Sabha.]

*270. [*Transferred to the 10th June*, 1971.]

REMOVAL OF ZONAL RESTRICTION ON THE MOVEMENT OF FOODGRAINS

*271. SHRI K. C. PANDA :
SHRI SUNDAR MANI PATEL :
SHRI K. SUNDARAM :

Will the Minister of AGRICULTURE/ **कृषि मंत्री** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the light of the record crop of foodgrains this year, Government are proposing to remove the zonal restrictions imposed on the movement of the foodgrains;

(b) if so, by when; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor and whether Government propose to reorganise the zones and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE/ **कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री** (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Zonal restrictions are reviewed periodically. Zonal restrictions exist now mainly in respect of rice. The movement of wheat and wheat products is now free throughout the country excepting the statutorily rationed areas of West Bengal. The restrictions on the movement of coarse grains have also been relaxed in all the major producing areas. The restrictions on the movement of rice were reviewed at the Chief Ministers' Conference held at New Delhi in September, 1970. It was agreed that these restrictions should continue during the crop year 1970-71 with a view to maximising internal procurement in the context of Government's decision to stop all concessional imports after 1971.

DAMAGE CAUSED TO THE ALLOY STEEL PLANT TRANSFORMER

*272. SHRI KRISHAN KANT :
SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA :
DR. SALIG RAM :
SHRI ARJUN ARORA :

Will the Minister of STEEL AND

†[ ] English translation.

MINES/इस्पात और खान मंत्री be pleased to state :

(a) whether the 50 Tons transformer of Alloy Steel Plant was damaged due to negligence ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES/इस्पात और खान मंत्री (SHRI S. MOHAN KUMARAMANGALAM) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

देहाती क्षेत्रों में बाजार

*273. श्री लाल आडवाणी :
श्री सुन्दर सिंह भंडारी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एप्लाइड इकानामिक रिसर्च की राष्ट्रीय परिषद् की एक गोष्ठी में यह कहा गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि तथा उन्नति तेज़ करने के लिए वर्तमान दो हजार के बजाय 14 हजार बाजारों का बनना नितांत आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†[MARKETS IN RURAL AREAS

*273. SHRI LAL K. ADVANI :
SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI :

Will the Minister of AGRICULTURE/कृषि मंत्री be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it was stated in a seminar of the National Council of Applied Economic Research that instead of the existing two thousand markets it is very essential to build up fourteen thousand markets in order to step up economic activities and progress in the rural areas of the country; and

(b) if so, what is the reaction of Government and what action is being taken in this regard?]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जानकारी देते हुए एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अप्रैल, 1971 में बाजार नगरों तथा क्षेत्र विकास (मार्किट टाउन्स एण्ड स्पेशल डिवेलपमेंट) के सम्बन्ध में आयोजित विचार गोष्ठी के संदर्भ में तैयार किये गये एक भूमिका कागजात में बताया गया था कि एक विपणन केन्द्र द्वारा 12 मील व्यास के क्षेत्र में समुचित रुप से सेवा की जा सकती है। 12,500 से 14,000 बाजार नगरों की आवश्यकता होगी, परन्तु इस कागजात में आवश्यकता के इन आंकड़ों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया था ।

पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त, विचार गोष्ठी अपनी अन्तिम चर्चाओं में इस निर्णय पर पहुंची कि अनासम्बन्धित बाजारों की सुव्यवस्थित श्रृंखला पहले से ही विद्यमान अत: नये बाजारों नगरों की स्थापना की अपेक्षा इन बाजारों को सशक्त बनाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये ।

(ख) विचार गोष्ठी द्वारा नये बाजार नगरों की स्थापना का कोई सुझाव नहीं दिया गया है, अत: प्रश्न ही नहीं होता ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE/कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) and (b) A statement containing the information is placed on the table of the Sabha.

STATEMENT

(a) It was stated in a background paper prepared in connection with a Seminar on Market Towns & Spatial Development organised in April, 1971 by the National Council of Applied Economic Research that on the basis that a market centre can adequately

†[ ] English translation.